भारत सरकार
जनजातीय कार्य मंत्रालय
लोकसभा
अतारांकित प्रश्न संख्या **5481**
उत्तर देने की तारीख: 03.04.2025

ओडिशा में ट्राइफेड की पहल

5481. श्री सुकान्त कुमार पाणिग्रही:
क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान ओडिशा के कंधमाल में जनजातीय कारीगरों को सहायता प्रदान करने तथा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जनजातीय हस्तशिल्प, हथकरघा और वन उपज के विपणन को बढ़ावा देने के लिए भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ (ट्राइफेड) द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं और पहलों का ब्यौरा क्या है;

(ख) वन धन योजना और अन्य ट्राइफेड कार्यक्रम जो कौशल विकास, मूल्य संवर्धन और हल्दी और शहद जैसे वन-आधारित उत्पादों के विपणन पर केंद्रित हैं, से कंधमाल के जनजातीय समुदायों को किस हद तक लाभ मिला है;

(ग) कंधमाल के जनजातीय उत्पादों के लिए आपूर्ति श्रृंखला, बाजार संपर्क और बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए किए गए वित्तीय आवंटन और मौजूदा तथा भविष्य की योजनाओं का ब्यौरा क्या है तथा इसकी प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए निगरानी तंत्र क्या हैं; और

(घ) क्या सरकार का विचार जनजातीय उत्पादों और उद्यमिता में अनुसंधान, प्रशिक्षण और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए कंधमाल में जनजातीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना हेतु विशेष सहायता प्रदान करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्यमंत्री
(श्री दुर्गादास उइके)

(क) से (घ) भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ लिमिटेड (ट्राइफेड) कंधमाल, ओडिशा सहित देश भर में जनजातीय समुदायों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय की "प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन" (पीएमजेवीएम) योजना को लागू कर रहा है। इस योजना के तहत, जनजातीय कारीगरों को सूचीबद्ध करना और उनसे विभिन्न जनजातीय उत्पादों की खरीद करना, जनजातीय समुदायों के लिए आजीविका के अवसरों को पैदा करने की एक मुख्य गतिविधि है। इसे हासिल करने के लिए, ट्राइफेड ट्राइब्स इंडिया आउटलेट्स, ई-कॉमर्स और प्रदर्शनियों के माध्यम से जनजातीय उत्पादों का खुदरा विपणन करता है। अब तक ओडिशा राज्य से 130 जनजातीय आपूर्तिकर्ताओं/उत्पादकों को ट्राइफेड द्वारा सूचीबद्ध किया गया है।

इसके अलावा, लघु वनोपज (एमएफपी)/गैर-एमएफपी के मूल्य संवर्धन के लिए वन धन विकास केंद्र (वीडीवीके) की स्थापना के लिए राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों (एसआईए) को वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है। इसके साथ, न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर 87 सूचीबद्ध एमएफपी वस्तुओं की खरीद के लिए राज्य सरकारों को परिक्रामी निधियां प्रदान की जाती हैं। 28.02.2025 तक, ट्राइफेड ने ओडिशा राज्य में 4,560 लाभार्थियों को जोड़ने वाले 16 वीडीवीके की स्थापना के लिए ₹240.00 लाख की राशि मंजूर की है। इसके साथ, वित्तीय वर्ष 2024-2025 के दौरान, आईटीसी के साथ बी2बी सहयोग के तहत ट्राइफेड ने प्रगति वीडीवीके, दारिंगबाड़ी, कंधमाल द्वारा आईटीसी को 26.25 लाख रुपये मूल्य की 15 मीट्रिक टन हल्दी की बिक्री को आगे बढ़ाया।

*****